IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 4, October-December, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971 (ONLINE)

भारत के विदेष नीति में इरान कि बदलती राजनीति

चन्दन कुमार

शोध-छात्र राजनीति विज्ञान विभाग

ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा (बिहार)

शोध.सार

अमेरिका के राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नाकेबंदी की घोशणा कर दी है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत जलडमरूमध्य के बाहर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि अमेरिकी वायुसेना अपनी अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों के साथ पूरे मार्ग को सी करने की कोषिष में जुटी है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन क्षेत्र में स्थिति अभी स्पश्ट नहीं है। कि एक बड़ा कारण समुद्र में ईरान की ओर से बिछाई गई बारूदी सुरंगे भी हैं। अगले 24–48 घंटों में स्थिति स्पश्ट होने की उम्मीद है। भारत स्थिति देखकर आगे की राह तय करेगा।

भारत का षुरूआती आकलन है कि अगर अमेरिकी प्रतिबंध प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो यह उसके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों तक सीमित है। जबकि ईरान के साथ भारत का कारोबार बहुत सीमित है। होर्मुज में भारत के जो 15 जहाज फंसे हैं, वे सभी गैर–ईरानी बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर आ रहे हैं। बहरहाल, इस नाकेबंदी के चलते ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे– बंदर अब्बास (सबसे बड़ा कंटेनर और बहुउद्देषीय बंदरगाह), खार्ग (ईरान का प्राथमिक तेल निर्यात टर्किनल, जहां से 90 प्रतिषत कच्चा तेल निकलता है), असलूयेह (गैस और पेट्रीकेमिकल निर्यात का केंद्र), बंदर इमाम खुमैनी, बंदर–ए– महषहर और बंदर–ए–बुषहर से आने वाले सभी जहाजों पर रोक लग जाएगी। वहीं गैर–ईरानी बंदरगाहों जैसे संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा (भारत के लिए जरूरी), जेबेल अली और खलीफा पोर्ट, सऊदी अरब के रास तनुरा, कतर कुवैत और इराक के कुछ टर्मिनल्स से तेल– गैस लेकर आने वाले जहाजों को अमेरिका सक्रिय मदद व सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत के कुल तेल आयात का 40 से 55 प्रतिषत इन्हीं गैर–ईरानी बंदरगाहों से आता है।

शब्द कूंजी– व्यापार, ऊर्जा, आयात, खाद्य आपूर्ति, बंदरगाह, कच्चा तेल।

प्रस्तावनाः

विदेष मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, 'सरकार होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी।

व्यक्तिविषेश नेतृत्व के कारक

भारत–ईरान मैत्री की षर्तों तथा सीमाओं को समझने में व्यक्तिविषेश नेतृत्व के कारकों के व्याख्यात्मक मूलय सीमित ही प्रतीत होते हैं। घरेलू दर्षकों के अंदर भारत–ईरान संबंधों को अत्यधिक मूल्यवान समझाा जाता है तथा इसे विवादास्पद नहीं माना जाता। यदि भारत तथा ईरान को अपनी योजनाओं पर तथा अंतर्राश्ट्रीय पटल की घटनाओं से असंयत छोड़ दिया जाता तो दोनों देष बहुत कुछ उपार्जित कर पाते यद्यपि, कुद नेतागणों को भारत–ईरान संबंधों को पुनर्जीवित करने के नवीकृत प्रयत्नों के साथ दृढ़ता से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री राव, जिन्होंने भारती विदेष तथा घरेलू नीतियों को नयी आकृति प्रदान करने की षुरूआत की, ने ईरान को विकसित करने का कदम उठाया। इसके फलस्वरूप उनका सन् 1993 का राजकीय़ दौरा हुआ। (राव ने दलाई लामा से भी दूरी बनाई रखी ताकि तिब्बत पर भारत के दृश्टिकोण एवं निर्वासित तिब्बती को षरण दिए जाने के बारे में चीनी चिंताओं को षांत रखा जा सके।) उनकी गणना सफल सही। सन् 1994 में पाकिस्तानी प्रधनमंत्री बेनजीर भुट्टो ने जिनेवा में संयुक्त राश्ट्र मानवाधिकार आयोग में जम्मू और काष्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर प्रस्ताव पारित कराने का प्रयत्न किया। आंषिक रूप से चीन तथा ईरान के समर्थन के आभाव के कारण वे नाकाम रहीं। राव के ईरानी तद्रूप राश्ट्रपति रफसंजानी ने ईरान की ओर से मैत्री का नेतृत्व

किया। रफसंजानी के सन् 1995 के दौरे ने वाषिंगटन का घ्यान आकर्शित किया काफी हद तक इस कारण कि यह (अमेरिकी) वित मंत्री रूबिन के भारत दौरे के समय हुआ–तथा कथित तौर पर उसे पीछे भी छोड़ दिया'। सन् 1993 तथा सन् 1995 के दौरों ने ईरान की सहायता की क्योकि इन दौरों ने तेहरान के एकाकीकरण के अमेरिकी प्रयासों को दुर्बल किया तथ व्यापक एषियाई पटल पर उसकी पदोन्नति एक महत्त्वपूर्ण कर्ता के रूप में हुई।

इसी प्रकार, खातमी तथा बाजपेयी दोनों प्रबल नेता थे। खातमी का चुनाव सन् 1997 में एक संषोधक के रूप में हुआ था तथा पूरा विष्व अंतर्राश्ट्रीय संबंधों के प्रति उनकी उस पद्धति से निस्तब्ध था, जो 'सभ्यताओं के संवाद' पर केंद्रित थीं। भारतीय विदेष नीति को उसके तृतीय विष्ववाद, आदर्षवाद तथा नीतिवाद के नेहरूवादी जड़ों से निकाल व्यवहारवाद तथा यथार्थवाद से अवगत नीति की ओर परिवर्तित करने का श्रेय वाजपेयी को दिय जाता है। (अन्य लोगों का तर्क है कि इस बदलाव का आरंभ सन् 1990 के बाद से ही जारी था।) वाजपेयी की नेतृत्व में भारत ने अनेक राजधानियों, जिसमें वाषिंगटन भी षामिल है, के साथ महत्त्वपूर्ण प्रगति की।

राष्ट्रपति अहमदीनजाद ने भारत के साथ इस संबंध को प्रत्यक्ष रूप से तथा निरंतर तौर पर प्राथमिकता नहीं दी हालाककि उन्होंने आवष्यकता पड़ने पर प्रयास किए ताकि अल्पतम प्रगति का बना रहना सुनिष्चित रहे, उनके नेतृत्व में बहुत कम ही भव्य विकास हुए हैं। इसके बजाय उनका राश्ट्रपति पद विदेष में अंतर्राश्ट्रीय विरोध तथा देष में आर्थिक रूप से विनाषकारी नीनियों से चिहिनत रहा। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रति ईरान के उदीयमान समीन ने दिल्ली को परेषान किया है। तालिबान तथा समवर्गी लड़ाकों ने अफगानिस्तान में कई सारे भारतीय श्रमिकों की हत्या की है, जिस कारण हाल के वर्शों में भारत इस मुद्दे को तेहरान के साथ उठाने हेतु प्रेरित हुआ। मनमोहन सिंह ने, अपनी ओर से, भारत के जटिल अंतर्राश्ट्रीय संबंधों की पूर्णता को बनाए रखने में प्र्याप्त क्षमता का प्रदर्षन किया है। परंतु वे वाजपेयी की तुलना में कम निर्भीक रहे हैं तथा कभी–कभी भीरू भी रहे हैं, जैसा कि वामपंथी तत्वों का मुकाबला करने में उनकी राजनैतिक सुस्ती से प्रमाणित हुआ जो भारत– अमेरिका असैन्य परमाणु संधि का ध्वंसन करना चाह रहे थे। अहमदीनेजाद तथा सिंह, दोनों ने अपने देषों की विभिन्न संधियों में संबोधित अधिक विवादपूर्ण मुद्दों की बजाय ऊर्जा राजनीति तथा अफगानिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया है।

संभवतः, अंतर्राश्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े संरचनात्मक कारक भारत–ईरान संबंधों के विस्तार– क्षेत्र को निरूद्ध करन जारी रखेंगे। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संरचनात्मक रूकावटें घरेलू राजनीतिक चिंताओं को अधिक बढ़ा देंगी। विषेश रूप से क्योकि ईरान संभवतः और अधिक एकाकीकृत हो जाएगा, भारतीय सार्वजनिक और निजी कताओं के लिएईरान में निवेष, विषेशकर बड हाइड्रोकार्बन अवसंरचनाओं में, अधिक महंगा और जोखिम भरा हो जाएगा। फिर भी, भारत को अपने विकास तथा षक्ति प्रक्षेपण को जारी रचाने के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवष्यकता है। तथापि, ईरान के साथ आचरण की चुनौतियों तथा निरंतर कड़े होते प्रतिबंधों के मद्देनजर, संभव है कि भारत षीघ्र ऊर्जा आपूर्ति हेतु अन्यत्र देखेगा। ऐसा वह ईरान में सक्रिय रहते हुए करेगा तथा इस बात की आस में रहेगा कि ईरान अंतर्राश्ट्रीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर ले। (भारत का प्रतिद्वंद्वी चीन भी इसी प्रकार ईरान तथा अन्य क्षेत्रों– जैसे कि सूडान,बर्मा तथा मध्य एषिया–में संबद्ध है जहॉ भारत सक्रिय है।) ऊर्जा की चिंताओं के आलावा भारत तथा ईरान, दोनों अफगानिस्तान में साथ कार्य जारी रखने हेतु अपेक्षित हैं, भारत संभावित रूप से ईरान के चाबहारबंदरगाह समूह में संबंधित अवसंरचना की परियोजनाओं को जारी रखेगा। तथापि, सुरक्षा ने पहले ही अफगानिस्तान में प्रगति को अवरूद्ध किया हुआ है तथा ईरान द्वारा तालिबान का निरंतर समर्धन तेहरान के साथ और कुछ करने की रूचि को कड़वा कर सकता है। स्पश्ट रूप से, यदि ईरान परमाणु अस्त्र देष बनने की भारत की अपनी महत्वाकांक्षाऍ भी इस क्षेत्र में ईरानी व्यवहार के प्रति उसकि अवस्थिति को आकर प्रदान करेंगी। हालांकि ये संरचनात्मक कारक भारत–ईरान संबद्धता के विस्तार–क्षेत्र को सीमित करेंगे, भारत के क्षेत्रीय हित चिरस्थायी हैं। ये हित दिल्ली को मध्य एषिया में वांछित प्रवेष मार्ग तथा ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने हेतु ईरान के साथ कार्य करने के रास्ते ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारत इन संरचनात्मक

सीमाओं तथा उनके द्वारा थोपी गई संबंधित घरेलू चुनौतियों के कारण ईरान के साथ संबद्ध होने के प्रयासों का परित्याग करेगा।

उदेश्य

1. चारबहार बंदरगाह को विकसित करना है।
2. ऊर्जा जरूरत के लिए ईरान से आपूर्ति बनाये रखन का।
3. कृशि टतप्ज्ञछज्ञै। (जैसे चावल, चाय, चीनी) दबाओं का निर्यात करना।
4. द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना।

षोध विधिः

षोध नियमों के अनुसार प्रस्तुत षोध सैद्धांतिक विष्लेशणात्मक, तुलनात्मक एवं नीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस षोध कार्य हेतु द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया। द्वितीयक स्त्रोतों के तहत आवयष्क सामग्री विभिन्न राश्ट्रीय पुस्तालयों इंटरनेट एवं षोध संस्थानों आदि में अपलब्ध साधनों के अलाावा प्राचीन संदर्भ ग्रंथों से एकत्र किया जाना अनुमान्य है। इन संदर्भ आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगो के प्रंकाषनों, आत्मलेखों समाचार पत्र–पत्रिकाओं एवं राजनैतिक दलों के घोशणा पत्रों इत्यादि के लेखन सामग्री संग्रहित कर विष्लेशणात्मक अध्ययन है।

कम से कम आने वाले कुछ वर्शों में घरेलू कारणों से भारत–ईरान संबंध संभवतः महत्वपूर्ण बने रहेंगे। साथ ही संभवतः, ये संबंध, ऐसे समय में जब वाषिंगटन के साथ भारत के संबंध सबसे करीबी हैं, भारत की स्वतंत्र विदेष नीति का एक वाचक भी बने रहेंगे। यद्यपि, यह स्पश्ट नहीं है, कि ऐसा होगा ही। क्लेशित भारतीय मुसलमानों, जो भारत की गठबंधन–चालित राजनीतिक व्यवसाी के महत्वपूर्ण मतदाता–वर्ग हैं, को यह संबंध षांत करने में कितना सक्षम होगा, यह षंकास्पद है। हालांकि ईरान ने कष्मीर पर अपनी अवस्थिति को अनेक बार संयमित किया है, उसने इस्लामिक सहयोग सम्मेलन (ओआईसी) जैसे मंचों पर कई बार कष्मीर पर पाकिस्तान के दृश्टिकोण का समर्थन किया है। भारतीय लोग तालिबान को नापसंद करते हैं, जिसने भारत में इस्लामी आतंकवाद में योगदान दिया है। सन् 2006 के मुंबई रे धमाकों में ईरान की संभवित भागीदारी के साक्ष्य (कितने भी कम) ने कुछ भारतीयों में ईरान के प्रति संदेह पैदा किया और परमाणु–सषस्त्र ईरान के लिए भारत सरकार तथा राज्यतंत्र में न के बराबर समर्थन है। इसके विपरीत, अमेरिका की विवादास्पद नीतियों, जैसे कि सन् 2003 में इराक पर आक्रमण के बावजूद, भारत–अमेरिका संबंध को भारत में बड़े पैमाने पर समर्थ प्राप्त है।

विकट संरचनात्मक बाधाओं तथा मौजुदा यथास्थिति में महत्वपुर्ण बदलाव लाने की अनिष्चित घरेलू अभिप्रेरणाओं के मद्देनजर, तार्किक रूप से भरतीय तथा ईरानी नेतृत्व का मूल्य इन चुनौतियों का मार्गनिर्देषन करने में महत्वपूर्ण अपूर्वानुमेय घटक होंगे। कुल मिलाकर, दोनों राजधानियों में प्रबल नेताओं– जो इन विभिन्न बाधाओं को सफलतापूर्वक सुलझा सकें तथा एक नया एवं साहसी मार्ग ले सकें– के आगमन को छोड़कर, संरचनात्मक तथा घरेलू कारक भारत–ईरानी मैत्री पर एक वास्तविक सीमा थोपते हैं तथा द्विपक्षीय संबंधों में मौलिक परिवर्तन की संभावना प्रस्तुत नहीं करते ।

निश्कर्शः–

हालांकि ईरान ने कष्मीर पर अपनी अवस्थिति को अनेक बार संयमित किया है, उसने इस्लामिक सहयोग सम्मेलन (ओआईसी) जैसे मंचों पर कई बार कष्मीर पर पाकिस्तान के दृश्टिकोण का समर्थन किया है। भारतीय लोग तालिबान को नापसंद करते हैं, जिसने भारत में इस्लामी आतंकवाद में योगदान दिया है। सन् 2006 के मुंबई रे धमाकों में ईरान की संभवित भागीदारी के साक्ष्य (कितने भी कम) ने कुछ भारतीयों में ईरान के प्रति संदेह पैदा किया और परमाणु–सषस्त्र ईरान के लिए भारत सरकार तथा राज्यतंत्र में न के बराबर समर्थन है खातमी तथा बाजपेयी दोनों प्रबल नेता थे। खातमी का चुनाव सन् 1997 में एक संषोधक के रूप में हुआ था तथा पूरा विष्व अंतर्राश्ट्रीय संबंधों के प्रति उनकी उस पद्धति से निस्तब्ध था, जो 'सभ्यताओं के संवाद' पर केंद्रित थीं। भारतीय विदेष नीति को उसके तृतीय विष्ववाद, आदर्षवाद तथा नीतिवाद के नेहरूवादी जड़ों से निकाल व्यवहारवाद तथा

यथार्थवाद से अवगत नीति की ओर परिवर्तित करने का श्रेय वाजपेयी को दिय जाता है। (अन्य लोगों का तर्क है कि इस बदलाव का आरंभ सन् 1990 के बाद से ही जारी था।) वाजपेयी की नेतृत्व में भारत ने अनेक राजधानियों, जिसमें वाषिंगटन भी षामिल है, के साथ महत्त्वपूर्ण प्रगति की

संदर्भ – सूची

1. लक्ष्मी तथा एमिली वैक्स (2008), इण्डियाज गवर्नमेंट विन्स पार्लियामेंट कॉन्डिेनन्स बोट, वाषिंगटन पोस्ट पृश्ठ सं0–171
2. 'गैप्स टु फिल' द हिन्दू (ई–पुस्तक),(2008), अक्टूबर पृश्ठ–172
3. मार्क टाउनसेन्ड (2008) स्पेषल फोसेज फाइंड प्रुफ ऑ ईरान सप्लाइंग तालिवान विद इक्विपमेंट टु फाईट ब्रिटिष द गार्जियन, 22 जुन पृश्ठ सं0–173
4. सुमित गांगुली,(2018) भारत की विदेष नीति पुरावलाकेन एवं संभावनाएँ पृश्ठ सं0–170
5. जे0 एन0 दीक्षित,(2012) भारतीय विदेष नीति पृश्ठ सं0– 288
6. जे0 एन0 दीक्षित,(2012) भारतीय विदेष नीति पृश्ठ सं0–314
7. तपन विस्वाल (2016) अंतराश्ट्रीय संबंध पृश्ठ सं0– 107
8. तपन विस्वाल (2016) अंतराश्ट्रीय संबंध पृश्ठ सं0– 109
9. सी0क्रिस्टीन फेयर (2008) पाकिस्तान रिलेषन्स विद सेन्ट्रल एषिया इज पास्ट प्रोलॉग पृश्ठ सं0– 201–271
10. सुमित गांगुली (2018) भारत की विदेष नीति पुनरावलाकन एवं संभावनाएँ पृश्ठ सं0– 165